RAJYA SABHA

Friday, the Wth—March, 1989 119th Phalguna, 1910 (Saka) The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman *in the Chair.*

RAL ANSWERS TO QUSTIONS

राष्ट्रीय बीज विकास योजना का प्रभाव

*221. **श्री अजीत जोगी:†**
श्री पृथ्वी माझी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गयी राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना का तिलहन उत्पादन पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कितनी सहायता दी गयी है और इस राज्य में तिलहनों के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) तिलहनों के उत्पादन में देश के कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है?

विवरण

(क) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के कार्यान्वयन से मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सातवीं योजना (1985-89) के पहले चार वर्षों के दौरान देश में तिलहनों के उत्पादन में बढ़ता हुआ रुख दिखाई पड़ रहा है। यह नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है:—

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन में)
1985-86	108.33
1986-87	112.70
1987-88	123.78
1988-89	145.00-155.00 (अस्थाई अनुमान)

†सभा में यह प्रश्न श्री अजीत जोगी द्वारा पूछा गया।

(ख) सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान संभावित व्यय (केन्द्रीय शेयर के रूप में) 52.00 करोड़ रुपए है।

(ग) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को 5.00 करोड़ रुपए (केन्द्रीय शेयर) की वित्तीय सहायता दी गई है। सूखे के बावजूद, मध्य प्रदेश में तिलहनों का उत्पादन, जो 1985-86 में 14.16 लाख मी. टन था, बढ़कर 1987-88 के दौरान 14.65 लाख मी. टन हो गया। खरीफ, 1988-89 के दौरान, 16.00 लाख मी. टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक उत्पादन से अधिक है।

(घ) तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके।

श्री अजीत जोगी: मान्यवर, जहां एक ओर तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना लागू की जा रही है और उसके अच्छे परिणाम आये हैं, जैसा उत्तर में दिया गया है, वहीं दूसरी ओर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका सीधा अहम् संबंध तिलहन के उत्पादन से है, उसकी तरफ शासन का ध्यान नहीं गया है और वह है तिलहन के सही और वाजिब मूल्य किसान को मिलना।

इस साल अच्छी मानसून होने के कारण और सरकार तथा किसान की मेहनत के कारण बहुत अच्छी फसल हुई, पर इस साल हम देख रहे हैं कि सभी तिलहन के मूल्य बहुत कम रहे हैं, चाहे मूंगफली हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, तिल हो, सब के मूल्य बहुत कम रहे हैं। सोयाबीन का मूल्य पिछले साल जबकि सात सौ रुपये क्विंटल था, इस समय अब तीन सौ, साढ़े तीन सौ रुपये क्विंटल में सोयाबीन बिक रहा है। एक ओर हम किसान को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तिलहन का उत्पादन करो जिससे देश आत्म-निर्भर हो, वहीं दूसरी तरफ हम किसान को तिलहन का सही मूल्य नहीं दे पा रहे हैं।

इसलिए मैं मंत्री जी से, आपके माध्यम से, जानना चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है जिससे किसान को तिलहन का सही मूल्य मिले, वाजिब मूल्य मिले? उसको पहले से बता दिया जाए कि यदि इस साल आप तिलहन की फसल का उत्पादन करोगे, तो आपको उसका कम से कम इतना मूल्य मिलेगा। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो शीघ्र ही देश तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और किसान ज्यादा से ज्यादा तिलहन की फसलों की पैदावार लेगा।

मैं मंत्री महोदय के जानना चाहता हूं कि इसके विषय में समर्थन मूल्य या अन्य कोई योजना जो सरकार के पास विचाराधीन है, उसको सरकार किस तरह से लागू करेगी?

श्री भजन लाल: सभापति जी, यह ठीक बात है कि इन दिनों बहुत थोड़ी सी भावों में गिरावट आई है। खास करके... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी: बहुत अधिक आई है। मैंने बताया है कि सात सौ भाव का तीन सौ पचास हो गया है, आधा हो गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: 50 फीसदी गिरावट आई है।

श्री भजन लाल: 50 फीसदी नहीं है, कुछ गिरावट आई है। सरसों में भी कुछ भाव मंदा हुआ है, लेकिन सभापति महोदय, आप जानते हैं कि सपोर्ट प्राइस जिन-जिन चाजों की हम तय करते हैं, उनकी सपोर्ट प्राइस बहुत नीचे जाए, तो सरकार बीच में आती है ताकि किसान को, जो सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने तय की है, उसके मुताबिक उसको भाव मिले। सपोर्ट प्राइस से नीचे किसी भी चीज का भाव नहीं गया, लेकिन हमेशा हमारी यह कोशिश रही है कि किसान को अच्छा भाव यानि लाभकारी मूल्य मिले।

श्री सभापति: तिलहन के लिए सपोर्ट प्राइस आपने रखी है।

श्री भजन लाल : सपोर्ट प्राइस जो रखी है, उससे भाव नीचे नहीं गया है।

श्री सभापति : मि॰ जोगी कह रहे हैं कि तिलहन के लिए सपोर्ट प्राइस नहीं है। What is the correct position?

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: आप बता दें कि सपोर्ट प्राइस क्या है?

श्री भजन लाल: ऐसा है कि मूंगफली की है, कुछ चीजों की है और कुछ चीजों की नहीं है। सारे मुल्क में 21 चीजों का भाव सपोर्ट प्राइस के नीचे है। इक्कीस जिन्सों का सपोर्ट प्राइस भारत सरकार तय करती है और कुछ का नहीं करती है।

श्री सभापति: कौनसी चीजों का नहीं किया है?

एक माननीय सदस्य: तिलहन का बताइये।

श्री भजन लाल: मैंने कहा कि मूंगफली का भाव है, लेकिन मूंगफली की कीमत सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं गई है।

श्री सभापति: मूंगफली का तो है, बाकी और चीजों का?

श्री भजन लाल: बाकी और चीजों से सरसों का भाव वी सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य: दालों का क्या है?

श्री भजन लाल: जहां तक दालों का ताल्लुक है, दालों की सपोर्ट प्राइस नहीं है।

श्री सभापति: यह सवाल तिलहन पर है। दालों का तेल मत निकालो। ...**(व्यवधान)**

श्री भजन लाल : दालों की सपोर्ट प्राइस नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जिनका नहीं भी है तो भी भारत सरकार की कुछ जिम्मेवारी होती है कि किसान को ठीक भाव मिले। उसके लिए नैफेड को हम बीच में लाते हैं और उसने पिछले साल यहां तक कि आलू और प्याज भी परचेज़ किया है।

श्री सभापति : आप कोशिश करिये।

श्री भजन लाल : जो-जो इन्होंने बताया है उसको हम चैक करेंगे। अगर वाकई भाव कम है तो भारत सरकार से कहेंगे नैफेड वगैरह से कि वह इसकी परचेज़ शुरू करे ताकि इसके भाव स्थिर रह सकें।

श्री सभापति : आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री अजीत जोगी : सर, मैंने निवेदन किया था कि अगर पहले से ही घोषणा कर दें तो किसान प्रोत्साहित होकर ज्यादा पैदावार लेगा। मान्यवर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश वैसे तो देश

के पिछड़े हुए प्रांतों में से है, परन्तु सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश राष्ट्र में अव्वल नम्बर पर है, प्रथम नंबर पर है, पर एक बात खेदजनक है कि मध्य प्रदेश में जो प्रति हेक्टेयर सोयाबीन का उत्पादन है वह 7 क्विंटल आता है जबकि विश्व के जो दूसरे उन्नत राष्ट्र हैं वहां 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक यह उत्पादन हो रहा है। पिछले दो-तीन वर्षों में शासन की तरफ से इंदौर और मालवा के किसानों को बायो-टैकनोलोजी के अंतर्गत राइजोबियम कल्चर नाम का फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया गया था जिसका इस्तेमाल करने से किसानों के उत्पादन में दुगुनी वृद्धि हुई। पर यह भी खेदजनक बात है कि थोड़ा-सा राइजोबियम कल्चर उपलब्ध कराने के बाद अब वह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जबकि किसान तो कह रहे हैं कि हमें वह एक टैक्नोलोजी दी जाए, पर शासन की तरफ से हम वह टैक्नोलोजी उनको नहीं दे पा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि मध्य प्रदेश को जितनी उसकी आवश्यकता है उतना राइजोबियम कल्चर उपलब्ध करा दिया गया तो मध्य प्रदेश अकेला ही राष्ट्र को तिलहन के उत्पादन में आत्म-निर्भर कर सकता है।

श्री सभापति : आप यह कल्चर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

श्री अजीत जोगी : इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या बायो-टैक्नोलोजी के इस बायो-फर्टिलाइज़र के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में कोई केन्द्र स्थापित करेंगे और मध्य प्रदेश के किसानों को प्रचुर मात्रा में बायो-फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जाएगा जिससे सोयाबीन के उत्पादन में दुगुनी वृद्धि हो और राष्ट्र में हम आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकें?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, खाद तो हम ज्यादा डालने के लिए किसानों को प्रेरित करते हैं।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, यह विशेष कल्चर की बात कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : लेकिन दूसरा इन्होंने कल्चर के बारे में जिक्र किया, उसमें सभापति महोदय, यह देखना पड़ता है कि जिससे आगे चल कर जमीन खराब नहीं हो जाए।

श्री सभापति : आप जनरल बात मत कीजिए। सोयाबीन की बात कीजिए।

श्री अजीत जोगी : सर, ऐसी कोई बात नहीं है उससे उत्पादन काफी बढ़ा है। उससे किसानों का उत्पादन दुगुना बढ़ा है।

श्री सभापति : सोयाबीन की बात कहिए और यह जो कह रहे हैं कि कल्चर जरूरी है उसके लिए आप प्रयास करें कि यह ज्यादा दिया जाए ताकि उत्पादन ज्यादा बढ़े।... (व्यवधान)

श्री भजन लाल : कृपा करके सुनने का प्रयास करें, मैं कहता हूं कि जो जरूरी है अगर वहां पर नहीं है तो हम उपलब्ध करायेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जबलपुर में बाकायदा हमने सैन्टर खोल रखा है इसके लिए और उस सैन्टर को हम कहेंगे कि जहां भी जरूरत है, आवश्यकता है उसको वह देखें और उसकी उपलब्धि करायें।

श्री सभापति : पूरा प्रयास करेंगे।

श्री भजन लाल : हां, पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अजीत जोगी : जबलपुर में ऐसा कोई केन्द्र नहीं है, सर। मालवा में सोयाबीन होता है। वहां के केन्द्र की मैं बात कर रहा हूं। मंत्री महोदय मेरे प्रश्न से हट कर जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं, जबलपुर में होता है यह तो मैं आपको बताता हूं, मालवा में भी हो तो यह सब उसको देख लेंगे।

श्री अजीत जोगी : सोयाबीन बैल्ट जो राइजोबियम कल्चर है वह वहां नहीं बन रहा है और मंत्री जी मेरे प्रश्न से अलग हटकर बता रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उपलब्धि उन्होंने दिखाई है प्रोविज़नल 1988-89 की उसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया था जिसके अगेन्स्ट यह उपलब्धि है और देश की आवश्यकता क्या है जिसके अगेन्स्ट आपने यह प्रोविज़नल प्रोडक्शन बताया है? मान्यवर, इसी का "बी"

पार्ट मेरा यह है कि कितने आयल सीड का हाई ब्रीड किस कीमत पर और किन-किन देशों से उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए आपने मंगाया है? हाई ब्रीड सीड किस कीमत पर, किन-किन देशों से और कितना मंगाया?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, जहां तक सीड मंगाने का ताल्लुक है ...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : पहले वाले का जवाब दीजिए।

श्री भजन लाल : वर्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, दोनों का जवाब दे दूंगा पहले वाले का पहले देता हूं। आपने पूछा कि टार्गेट क्या था और कितना उत्पादन हुआ? पिछले साल 1987 में आइल सीड 124 लाख टन पैदा हुआ। इस दफा हमारा टार्गेट 150 का था और हमारी उम्मीद है कि इस दफा हर हालत में हमारे मुल्क में 155 लाख टन आइल सीड पैदा होगा टार्गेट से ज्यादा होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : बहुत खुशी की बात है।

श्री भजन लाल : दूसरे जहां तक बीज बाहर से मंगाने का प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैंने आवश्यकता पूछी है। मैं यह कह रहा हूं कि आपने बताया कि देश में उत्पादन 150 लाख टन या 155 लाख टन होगा। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी आवश्यकता क्या है जिसके अगेन्स 150-155 टन होगा?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, हमारे मुल्क में आज खाद्य तेल की आवश्यकता 54 लाख टन की है और हमारे उत्पादन 155 से जो तेल बनेगा वह 50 लाख टन होगा अर्थात 4 लाख टन की हमारे पास कमी है। आप जानते ही हैं कि इसमें से 1/3 के तकरीबन तेल बनता है अगर 12 लाख टन और पैदा हो तो हमारी पूर्ति हो जाती है। खासकर हमारे मुल्क में जितना तेल चाहिए उतना टार्गेट 160 लाख टन का फिक्स किया है ताकि बाहर से तेल मंगाना न पड़े। मुझे सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को बताते हुए खुशी है कि पिछले साल जहां हमने एक हजार करोड़ रुपए का तेल बाहर से मंगाया था इस दफा बड़ी मुश्किल से 3-4 सौ करोड़ का ही मंगाना पड़ेगा। हमारे मुल्क में आइल सीड का इतना अच्छा उत्पादन हो गया है। अब जहां तक सीड बाहर से मंगाने का ताल्लुक है, भारत सरकार ने फैसला किया है कि मोटे अनाज, आइल सीड, पल्सेस, फल और सब्जी के बीज जहां कहीं से भी दुनिया में अच्छे मिलें वहां से किसान ला सकता है। जो सीड का काम करने वाले हैं, जिनको कि सीड का तजुर्बा है, वे लोग भी बाहर से ला सकते हैं। हमने फ्री हैंड दे दिया है ताकि हमारे मुल्क में इन सब चीजों का उत्पादन अच्छा हो सके।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। मैंने यह पूछा कि आइल सीड के लिए हाई ब्रीड सीड कितना मंगाया, किन-किन देशों से और किस कीमत पर मंगाया?

श्री सभापति : हाई ब्रीड सीड मंगाया था?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, हम ने ओपन कर दिया। सब ला सकते हैं। पहले बहुत थोड़ी मात्रा में मंगाया है और मंगाकर किसान को दिया भी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कितना और किस कीमत पर?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, अलग-अलग क्वालिटी का सीड है — सब्जियों का भी है, फलों का, फूलों का और आइल सीड का भी है। लेकिन जितनी जरूरत है उतना नहीं ला सके हैं हम। इसीलिए हमने फ्री किया है कि कोई भी प्रायवेट व्यक्ति, कोई भी किसान लाना चाहे तो ला सकता है। ...**(व्यवधान)** ...हमने बाकायदा लेबोरेटरी खोल दी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : महोदय, अगर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आप पूछ लीजिए। कितना मंगाया और किस कीमत पर और कहां से? बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : यह तो इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री रिप्लाय देगी?

श्री सभापति : यह बीज आपने किस मूल्य पर किन-किन देशों से मंगवाया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : नहीं तो कह दीजिए कि इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, यह जो इन्होंने पूछा कि कौन-कौनसा सीड बाहर से मंगवाया उसके डिटेल्स आंकड़े मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि जितनी आवश्यकता थी उतना बाहर से नहीं आया इसलिए हमने फ्री किया है कि यदि कोई लाना चाहे तो ला सकता है। कोई प्रोब्लम नहीं है।

SHRI RAOOF VALIULLAH : Sir, there has been a bumper crop of groundnut in Gujarat, thanks to a favourable monsoon. I would like to know from the hon. Minister whether the Union Government would instruct agencies like the NAFED to purchase groundnut from the fanners at an enhanced support price. 1 know there is a support price for groundnut. But would the support price be enhanced as desired by the Government of Gujarat and what has been the financial assistance to Gujarat under NDDP during the first three years of the Seventh Plan?

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि इस दफा गुजरात में मूंगफली की पैदावार काफी हुई है और जो सपोर्ट प्राइस है वह 430 रुपए क्विंटल है। अभी तक भाव वहां 430 रुपए क्विंटल से नीचे नहीं गया। हमारे पास इत्तिला आई थी कि कुछ क्वालिटी थोड़ी सी नरम है, उसका भाव 400 तक गया था लेकिन अभी पिछले 10-12 दिन से मार्केट में उसका भाव अच्छा हो गया है। अगर 430 रुपए से नीचे जाएगा तो टोटल भारत सरकार प्रोक्योअर करेगी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है।

अगले साल का जहां तक ताल्लुक है हम भाव तय करने जा रहे हैं। जो खरीफ की फसल बोई जाएगी, बोने से पहले भाव तय करके किसानों को बताएंगे कि अगले साल हम आपको इस-इस जीन्स का यह-यह भाव देने जा रहे हैं।

श्री सभापति: उनका कहना है कि अगले साल भाव थोड़ा ऊंचा कर दीजिएगा।...**(व्यवधान)**...

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसको हमने मार्केट में एन्टर होने के लिए कह दिया है और 500 करोड़ रूपए का स्पेशल इंतजाम करके डी०डी०बी० को दिया है ताकि किसानों का भाव नीचे नहीं जाए और भाव टिका रहे। इसी के साथ-साथ ही दूसरी बात इन्होंने कही कि आगे भाव ठीक करेंगे या नहीं..**(व्यवधान)**...

श्री रऊफ वलीउल्लाह : मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा है कि सैन्ट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस गुजरात को क्या दिया?

श्री सभापति: गुजरात को कुछ मदद दी है आपने पैसों की?

श्री भजन लाल : प्रदेश वाइस अगर आप कहें तो मैं आपको सबकी ...**(व्यवधान)**...

श्री रऊफ वलीउल्लाह : सबका नहीं, गुजरात का ही बता दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री भजन लाल : मैं आपको सबकी बता सकता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : सिर्फ गुजरात का मांग रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ज्यादा देने को तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भजन लाल : अटल जी, जो आप कहेंगे, उस पर विचार करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दो स्कीम्स हैं हमारी। एक-एन० ओ० डी० पी० है, जिसमें 50 प्रतिशत पैसा भारत सरकार का लगता है और 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट देती है। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : वह सिर्फ रकम पूछ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भजन लाल : लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने गुजरात को पिछले साल, 1988-89 जो चल रहा है, उसमें हमने 2 करोड़ रुपया दिया है। इसके अलावा दूसरी स्कीम जो है वह ओ० पी० टी० पी० की है, उसमें भी हमने गुजरात को दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिया होगा। जब इतना कह रहे हैं तो मान लेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल : नहीं मानेंगे तो हम आपको मनाएंगे। 1 करोड़ 92 लाख हमने उसमें दिया है।

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM : Mr. Chairman, Sir, in his reply the Hon. Minister has stated that the first four years of the Seventh Plan have been showing an increasing trend in production. Mr. Chairman, Sir, it is a misleading statement. Hon. Minister has conveniently omitted the year 1984-85 and 1983-84. In 1983-84 the production was 12. ...

MR. CHAIRMAN : He has given the figures from 1985-86. How do you say that he has omitted?

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM : He has conveniently omitted one year earlier, i.e. 1984-85. In that year the production was 12.95 lakh ...

MR. CHAIRMAN : The question of omitting comes when he starts from an earlier year and he has left out anything in between. He has started from 1985-86 and you cannot blame him for that. (*Interruptions)* You come to the point.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM : This increase does not correspond to increase in area under cultivation. In the year 1983-84, 18.69 million hectares were there which were increased to 20 million in 1984-85. But production is less. Even per hectare production is declining.

MR. CHAIRMAN : Has per hectare production declined in recent years? That is the question.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM : And what steps are going to be taken to increase production?

SHRI VIRENDRA VERMA : Is it increasing or decreasing?

MR. CHAIRMAN : Same thing; I have put it in short whether per hectare production is declining. That is what you are saying.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM : An overall production also does not correspond to the increase in area under cultivation. And what steps are being taken by the Minister to increase production?

श्री सभापति : क्या डिक्लाइन हुआ है और उसको आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बताइए।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, जो इन्होंने पूछा उसका पूरा जवाब मैं दूंगा, वरना इनकी तसल्ली नहीं होगी। इन्होंने कहा कि 1984 में ज्यादा हुआ और उसके बाद घट गया, एक तरह का इल्जाम लगाया।

श्री सभापति : ये कहते हैं कि एरिया बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन घट गया।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, प्रोडक्शन भी बढ़ा है पर हैक्टेयर, 1985-86 में मुल्क की ऐवरेज 570 किलो पर हेक्टेयर थी, 1986-87 में 605 हो गई, 1987-88 में 619 पर हैक्टेयर हो गई। इन्होंने पता नहीं कहां से आंकड़े इकट्ठा किए।

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM : Earlier it was more. Per hectare production in 1983-84 was more, and even...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, पर हैक्टेयर का हिसाब कितने रकबे पर निकाला गया?

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा कीजिए, बीच में क्यों बोलते हैं. यह सवाल तो आयलसीड का है जिसे रसोई के लिये बीबी खरीदती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बीबियां कहां से आ गईं? एक बीबी की बात तो मैं समझ सकता हूं ये बीबियां कहां से आ गईं?

श्री भजन लाल : तेल आपने खरीदा नहीं, आपको क्या पता। आप क्यों इस झगड़े में पड़ते हैं, इससे आपका ताल्लुक नहीं है क्योंकि आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं। महोदय, 1985-86 में 190 लाख हैक्टेयर में था, 1986-87 में 186.26 लाख हैक्टेयर हो गया और 1987-88 में 200 लाख हैक्टेयर में बोया गया यह आंकड़ों की बात है.

Action on the recommendations of the National Commission on Urbanisation

***222.** SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply to Starred Ouestion 209 given in the Rajya Sabha on the 25th November, 1988 and state :

(a) whether any action has been taken on the recommendations of the Nationa! Commission on Urbanisation headed by Shri Charles Correa; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The report of the Commission has been circulated to various Departments and Agencies of the Central Govts, as well as to all State Govts. / UT Administrations. The report was also discussed in the All India Conference of Housing Ministers, Urban Development Ministers and the Central Council of Local Government, and All India Conference of Housing Ministers, Urban Development Ministers and the Central Council of Local Government and All India Council of Mayors. The State Governments have agreed to forward their comments expenditiously-

2. A Task Force has been constituted to examine existing poverty alleviation programmes in terms of the benefits to the target groups and optimum utilisation of funds.

3. A Group of experts and officials has also been constituted to consider the recommendations of the Commission for re-organisation of the Central agencies for effective implementation of Urban Development and Housing Programmes,

4. The question of enhancing the outlay for urban sector is proposed to be taken up with the Planning Commission in the context of formulation of the Eighth Five Year Plan. Meanwhile it is proposed to expand the lending of HUDCO for urban infrastructure.

5. The Delhi Rent Control Act has already been amended.

6. The National Housing Bank has already been set up.

7. It is proposed to formulate an Action Plan based on the recommendations toibe accepted after taking into account the reactions from various agencies.

SHRI CHITTA BASU : Sir, as you know, the All lndia Mayors' Conference was recently held in New Delhi, and this Conference came to the conclusion that even Bombay and Delhi which allocated huge amount of their budgets, had nearly 50 per cent of the population living in squalid condition. The Mayors' Conference also observed that the Charles Correa Commission had recommended an immediate release of Rs. 150 crores each for the development of slums in Bombay and Calcutta during the current Plan period. Trie Conference also demanded that the Government should come out with concrete position regarding this National Commission on Urbanisation within three months, and particularly before the Ninth Finance Commission finalises its recommendations. May I know the reactions or responses of the Government in regard to these three specific issues raised by the All-India Mayors Conference?

श्री दलबीर सिंह : माननीय प्रधान मंत्री जी के पहल पर चार्ल्स कोरिया कमीशन का गठन 1985 में हुआ।